AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदा दस्तावेज के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का महत्वपूर्ण विश्लेषण

ORIGINAL ARTICLE

Authors
अर्चना कुमारी
शोधार्थी

डॉ. रेनू गुप्ता
शोध पर्यवेक्षिका
शिक्षा संकाय
संस्कृति विश्वविद्यालय
मथुरा, उत्तरप्रदेश, भारत

शोध सार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे राष्ट्र को एक न्यायसंगत और जीवंत ज्ञान समाज में लगातार बदलने में अमूल्य योगदान प्रदान करती है।यह नीति इस बात से सहमत है कि बड़ी भारी संख्या में ऐसे बच्चे ऐसे स्कूलों में जा रहे हैं जहाँ ऐसी भाषा में शिक्षा दी जाती है जो उन्हें समझ में नहीं आती। इसके चलते वे सीखना शुरू करने से पहले ही पिछड़ने लगते हैं और अंततः शिक्षा की प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं।राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा ज्ञान–अर्जन या ज्ञान निर्माण और तभी संज्ञानात्मक और सामाजिक गतिविधियों में सीधे–सीधे मध्यस्तता रहती है।इसमें बाल–विकास, बाल मनोविज्ञान और भाषा विज्ञान में हुए अध्ययन यह बताते हैं कि बच्चे अपनी मातृ भाषा में सबसे बेहतर सीखते हैं। नई शिक्षा नीति–2020 में प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में मातृभाषा को प्राथमिकता दिया गया है। इसमें बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयारी की गई है।

मुख्य शब्द

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा, मातृ भाषा, प्राथमिक शिक्षा.

परिचय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक भारत केन्द्रित शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है जो सभी को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके, हमारे राष्ट्र को एक न्यायसंगत और जीवंत ज्ञान समाज में लगातार बदलने में योगदान देती है।

उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य है:

1. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) में प्राथमिक शिक्षा का विश्लेषण करना।
2. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) में प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में मातृभाषा के प्राथमिकता का अध्ययन करना।

3. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) में बच्चों के प्राथमिक शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान के तरीकों का विश्लेषण करना।
4. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) का प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के विधियों का विश्लेषण करना।

शोध का महत्व

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2025 तक 3 से 6 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए मुफ्त, सुरक्षित, उच्च गुणवत्तापूर्ण, विकासात्मक स्तर के अनुरूप देखभाल और शिक्षा की पहुँच को सुनिश्चित करना है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में कक्षा–5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है, साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा–8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसके लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में समस्याओं के समाधन के तरीकों का विश्लेषण किया गया है।

स्कूल में विद्यार्थी उपस्थिति का अनुश्रवण, शिक्षण में पिछड़ रहे बच्चों की निगरानी, स्कूल से बाहर के (ड्रॉपआउट) बच्चों की सतत निगरानी, बच्चों के स्वास्थ्य में स्कूलों की भूमिका की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक शिक्षा का मूल्यांकन करना इस शोध का महत्व है।

वर्ष 2025 तक 3 से 6 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए मुफ्त, सुरक्षित, उच्च गुणवत्तापूर्ण, विकासात्मक स्तर के अनुरूप देखभाल और शिक्षा की पहुँच को सुनिश्चित करना NEP 2020 का उद्देश्य है। नई शिक्षा नीति–2020 में प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में मातृभाषा को प्राथमिकता दिया गया है। इसके साथ ही साथ तीन भाषाओं के फॉर्मुला को नई शिक्षा नीति–2020 के मसौदे में भी प्रमुखता के साथ शामिल किया गया है।

इसमें पहली व दूसरी कक्षा में भाषा व गणित पर काम करने पर जोर देने की बात नई शिक्षा नीति के मसौदे में है। इसके साथ ही चौथी व पाँचवीं के बच्चों के साथ लेखन कौशल पर काम करने पर भी ध्यान देने की बात कही गई है। भाषा सप्ताह, गणित सप्ताह व भाषा मेला व गणित मेला जैसे आयोजन करने की बात भी इस प्रारूप में लिखी गई है।

इसमें पुस्तकालयों को जीवंत बनाने व गतिविधियों को कराने पर ध्यान देने की बात कही गई है। इसमें कहानी सुनाने, रंगमंच, समूह में पठन, लेखन व बच्चों के बनाये चित्रों व लिखी हुई सामग्री का डिसप्ले करने पर ध्यान देने की बात कही गई है। शिक्षाक्रम में विषयवस्तु को बोझ कम करने का सुझाव दिया गया है ताकि मूलभूत अधिगम और तार्किक चिंतन को समृद्ध किया जा सके।

इसमें प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में बहुभाषिकता को प्राथमिकता के साथ शामिल करने की बात की गई है। यह समस्या राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों में दिखाई देती है। पहली से पाँचवी तक जहाँ तक संभव हो मातृभाषा को इस्तेमाल शिक्षण के माध्यम के रूप में किया जाये। जहाँ घर और स्कूल की भाषा अलग–अलग है, वहां दो भाषाओं के इस्तेमाल का सुझाव दिया गया है। बहुभाषिकता को समस्या के बजाय समाधन के रूप में देखने की बात को नई शिक्षा नीति–2020 के मसौदे में प्रमुखता के साथ रेखांकित किया है।

मात भाषा/स्थानीय भाषा में शिक्षा

भाषा से जुड़े मुद्दे शिक्षा के लिए सबसे अधिक महत्व रखते हैं। भाषा संवाद का माध्यम होने के अतिरिक्त किसी व्यक्ति, समाज और इसके सामुदायिक संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखने और इसके सम्प्रेषण का माध्यम भी है। किसी भी तरह के ज्ञान–अर्जन या ज्ञान निर्माण संज्ञानात्मक और सामाजिक गतिविधियों में भाषा सीधे–सीधे मध्यस्थता करती है। बाल–विकास, बाल मनोविज्ञान और भाषा विज्ञान में हुए अध्ययन यह बताते हैं कि बच्चे अपनी

मातृ भाषा में सबसे बेहतर सीखते हैं। 2 से 8 वर्ष की उम्र के दौरान बच्चों में अनेक भाषाओं को सीखने की गजब की क्षमता होती है।

मात भाषा/घर की भाषा में शिक्षा

यह सर्वविदित तथ्य है कि बच्चे सभी महत्वपूर्ण संकल्पनाओं को अपनी मातृ भाषा या अपने घर की भाषा में जल्दी और बेहतर सीखते हैं। यह नीति इस बात से सहमत है कि बड़ी भारी संख्या में ऐसे बच्चे ऐसे स्कूलों में जा रहे हैं जहाँ ऐसी भाषा में शिक्षा दी जाती है जो उन्हें समझ में नहीं आती। इसके चलते वे सीखना शुरू करने से पहले ही पिछड़ने लगते हैं और अंततः शिक्षा की प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं इसलिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि आरंभिक वर्षों में बच्चों की कक्षाएं उनकी अपनी भाषाओं में चलाई जाए।

सुरक्षा सुनिश्चित करना

स्कूल के रास्ते में या स्कूल के भीतर होने वाले उत्पीड़न की घटनाओं की वजह से स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों और अन्य बच्चों को ऐसी घटनाओं से बचाने के लिए संस्था प्रधान, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय स्तर पर कानूनी प्रक्रियाओं को लागू करने वाली संस्थाएं/निकाय परस्पर मिलकर काम करेंगे जिससे कि बदमाशों की पहचान की जा सके, उन्हें अनुशासित किया जा सके और आवश्यकता पड़ने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सके।

भागीदारी और सीखना सुनिश्चित करना

स्कूल में विद्यार्थी उपस्थिति का अनुश्रवणः सभी छात्रों को उपस्थिति पर नजर रखने के लिए स्थानीय स्तर पर शिक्षकों और के SMC के सहयोग से एक पारदर्शी और विश्वसनीय प्रणाली स्थापित की गयी है।

शिक्षण में पिछड़ रहे बच्चों की निगरानी

शिक्षक एडेप्टिव एसेसमेंट के द्वारा लगातार बच्चों के सीखने के प्रतिफलों का आकलन करेंगे जिससे कि उन बच्चों की पहचान की जा सके जो कि पिछड़ रहे हैं। इसके साथ ही शिक्षक ऐसे बच्चों के अभिभावकों से परामर्श कर इन विद्यार्थियों के लिए सीखने की व्यक्तिगत रणनीतियाँ निर्धरित करेंगे, जिसमें कि उन्हें उपचारात्मक शिक्षण के कार्यक्रमों जैसे कि NTP और RIAP से जोड़ा जा सके।

स्कूल से बाहर के (ड्रॉपआउट) बच्चों की सतत् निगरानी

सामाजिक कार्यकर्ताओं, संस्था–प्रधानों, समुदाय के सदस्यों और SMC के सहयोग से सभी ड्रॉपआउट बच्चों और गैर नामांकित (आउट–ऑफ–स्कूल) बच्चों के ट्रैक करने और उनका डेटाबेस बनाने के लिए क्षेत्र–विशेष के लिए उपयुक्त और स्थानीय रूप से प्रासंगिक तंत्र का विकास किया गया है।

निष्कर्ष

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में शिक्षा की पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी 6 प्रतिशत हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आँगनबाड़ी, बालवाटिका, प्री–स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है।

प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिक दी गयी है। राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा–3 तक के सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयारी की गयी है।

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल, जे.सी. (2021), *आधुनिक भारतीय शिक्षा,* शिप्रा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
2. कोठारी, ममता (2022), *शिक्षा और समाज,* अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
3. कौल, एल. (2021), *शैक्षिक अनुसंधन की कार्य प्रणाली,* विकास पब्लिसिंग हाऊस प्रा. लि. नोएडा।
4. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी)।
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020।

****